शिक्षकों को नहीं हुआ एरियर्स की 25 फीसदी राशि का भुगतान

शिक्षकों ने कहा लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए विभाग को

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोक सेवकों को हर सुविधा समय पर देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जवाबदार अफ सरशाही मुख्यमंत्री की इन उम्मीदों पर पानी फेर रही है। शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों के लंबित एरियर्स की राशि यह गवाही दे रही है। शिक्षकों के अनुसार सरकार ने प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी व अंतिम किस्त के आदेश जारी करते हुए 75 प्रतिशत राशि के भुगतान के निर्देश दिए हैं। वही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें सातवें वेतनमान के एरियर की 25 फ ीसदी राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जबकि सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर 2020 में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के निर्देश प्रसारित किए थे। प्रदेश भर में हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें सातवें वेतनमान की दूसरी किस्त के अलावा 24 और 30 साल सेवा उपरांत क्रमोन्नति की अंतर राशि का भुगतान नहीं हुआ है। प्रदेश भर से शिकायत मिलने के बाद समग्र शिक्षकों ने आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है जिन्होंने अकारण शिक्षकों की एरियर्स का भुगतान रोक रखा है।

आयुक्त को संबोधित पत्र में संगठन ने उल्लेख किया है सेवा पुस्तिका सत्यापन के नाम पर जिस प्रकार प्रदेश भर में कोषालयों और बाबुओं की मिलीभगत से व्यापक स्तर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सुविधा शुल्क के अभाव में शिक्षकों की एरियर की राशि रोकना संकुल केंद्रों का अधिकार बन चुका है। उस पर लगाम लगाई जाए!

Babu Gautam

सेवानिवृत्त शिक्षक भी भटकने को मजबूर

समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे का कहना है कि अधिकारी अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हैं। दुबे के अनुसार आयुक्त को लिखे पत्र में संगठन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवानिवृत्त शिक्षक अपने स्वत्वों के भुगतान के लिए महीनो संकुल केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। समय.समय पर सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन के बावजूद प्रतिवर्ष रिकवरी के हजारों प्रकरण सामने आ रहे हैं। हजारों मामले अदालतों में पेंडिग है। जिससे शिक्षक हलकान हैं। पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद रिटायर्ड शिक्षकों को महीनों पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है।

कैंप लगाकर किया जाए शिक्षकों की समस्या का समाधान

समग्र शिक्षक संघ मध्यप्रदेश के महामंत्री संजय तिवारी ने आयुक्त लोक शिक्षण से मांग की है कि प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय शिविर लगाकर शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही जानबूझकर प्रकरण लंबित रखने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। महामंत्री संजय तिवारी ने कहा कि यदि 15 दिवस के अंदर शेष अंतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो प्रत्येक जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूची उस जिले के कलेक्टर के साथ साथ आयुक्त लोकशिक्षण को भी प्रेषित की जाएगी।

स्कूल खुलने पर रोक, लेकिन डीईओ ऑफिस के पीछे सरकारी स्कूल में ही लग रही कक्षाएं

प्रबंधन ने कहा: हॉस्टल की छात्राएं आईं थीं स्कूल

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

प्रदेश सरकार ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहां 31 मार्च तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन राजधानी में ही इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा है।

तुलसी नगर क्षेत्र में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास स्थित शासकीय नवीन कन्या हायर सेकंडरी स्कूल में ही 10वीं और 12वीं की होस्टल में रहने वाली छात्राओं की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, नवीन कन्या स्कूल में सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं की छात्राओं को क्लास लगाने के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया था।

इसके बाद सोमवार दोपहर करीब 12 बजे कई छात्राएं कक्षाओं के बाहर बरामदे में खड़ी नजर आई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं होता दिखा।

इधर, इस मामले में स्कूल के प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में कोविड प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। स्कूल में बाहर की छात्राएं नहीं आ रही हैं। उन्होंने सिर्फ होस्टल में रहने वाली छात्राओं को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल आने की अनुमति दी है।

बोर्ड परीक्षा फार्म संशोधन में हो रही परेशानी: सिंह

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ब्लू प्रिंट में लगातार बदलाव के बाद अब एक बार फिर परीक्षा फार्म को लेकर विवादों में हैं। निजी स्कूल संचालकों ने कहा है कि माशिमं द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के आवेदन फार्म में संशोधन में परेशानी हो रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह का बताया कि प्राइवेट स्कूलों एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा फॉर्म में अधिकांश संशोधन अब तक नहीं हो पाए हैं। स्थिति यह है कि बच्चों के संशोधन की फीस तो जमा हो गई है, लेकिन संशोधन नहीं हुआ। जबकि मंडल का यह फरमान है कि परीक्षा के बाद कोई संशोधन नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मांग की है कि परीक्षा फॉर्म में कितने भी संशोधन हैं सब में सुधार करवाया जाए।

संज्ञान में आया है मामला

मामला हमारे संज्ञान में आया है। स्कूल में बाहर से किसी छात्रा को नहीं बुलाया गया है, जो छात्राएं हॉस्टल में रह रही है, सिर्फ वही मौजूद थी।

नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

Badri Gautam

नई शिक्षा नीति आई पर शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे

अरविंद पांडेय ● नई दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को नालंदा और तक्षशिला जैसी प्रतिष्ठा दिलाने की बातें तो हो रही है, लेकिन जब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे, तो यह मुकाम कैसे हासिल हो पाएगा। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है।

यह कमी भी कोई सौ-दो सौ शिक्षकों की नहीं है, बल्कि अकेले केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ही 14 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों की है, जहां फिलहाल शिक्षकों के छह हजार से ज्यादा पद खाली हैं। आइआइटी, एनआइटी और आइआइएम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर यह सवाल उस समय उठ रहे है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार तेजी से लागू करने में जुटी है। खास बात यह है कि नीति में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर चिंता जताई गई है, साथ ही कहा गया है कि जब तक शिक्षकों के खाली पदों को भरा नहीं जाएगा, तब तक नीति का फायदा मिलना मुश्किल है।

तीनों सेनाओं में एक लाख से ज्यादा पद रिक्त

नई दिल्ली(एजेंसी)। सेना के तीनों अंगों में एक लाख सात हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा करीब 86 हजार पद अकेले थल सेना में खाली हैं। राज्यसभा में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जूनियर कमीशन अधिकारियों एवं अन्य रैंक के 79,349 पद खाली हैं जबकि अधिकारियों के 6,975 पद रिक्त हैं। नौसेना में अधिकारियों के स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,044 पद जबकि नाविक एवं अन्य रैंक में 12,317 पद खाली हैं।

Badri Gautam

प्रत्येक विद्यालय के 5 सौ मीटर के दायरे में बनवाएँ स्पीड ब्रेकर्स

लोक शिक्षण संचालनालय के प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देश

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर

Badri Gautam

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए जिले के सभी स्कूलों के बाहर 5 सौ मीटर के दायरे में स्पीड ब्रेकर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क सुरक्षा संबंधित गाइडलाइन जारी की है।

आदेश में कहा गया है कि विद्यालय परिसर के मेन गेट के पास सड़क चिन्हों, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन इत्यादि बोर्ड लगाए जावें। विद्यालय प्रारंभ एवं समाप्ति के समय ट्रैफिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थी सुरक्षित सड़क पार कर सकें।

विद्यालयों में लगे प्रायवेट-सरकारी बस, ऑटो, वैन के चालकों-परिचालकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराया जाए। स्कूल वाहन ओव्हरलोड न हो। प्रत्येक विद्यालय के बाहर वाहन निर्धारित गति से अधिक न भागें इसका ध्यान रखा जावे। वाहन चालक तेज हॉर्न न बजावें, इससे संबंधित निर्देश स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।

शिक्षकों से तैयार करवाई 10वीं-12वीं की प्रश्न बैंक, नहीं किया भुगतान

97 शिक्षकों की बकाया है दस लाख रुपए की राशि

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल के तात्कालीन अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने राजधानी के निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्रश्न बैंक तैयार करने और मंडल के यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो तैयार करने के लिए लगाया गया था। इसमें मॉडल स्कूल के शिक्षकों को भी लगाया गया था, लेकिन इनके पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया, जबकि निजी स्कूलों के शिक्षकों के पारिश्रमिक का भगुतान नहीं किया गया। इस संबंध में निजी स्कूल के शिक्षकों ने मंडल के सचिव को ई-मेल के माध्यम से शिकायत की है। माशिमं ने निजी स्कूलों के शिक्षकों को वीडियो व प्रश्न बैंक मॉडरेशन कार्य के लिए प्रतिदिन 500 रूपए भगुतान करने का आदेश जारी किया था। एक शिक्षक से करीब 20 दिन कार्य करवाया गया, लेकिन उनके भत्ते भुगतान अब तक नहीं किया। वहीं मंडल के तात्कालीन अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया के चले जाने के बाद अब अन्य अधिकारी जानकारी ना होने का बहाना बना रहे हैं। अब निजी स्कूलों के शिक्षकों ने मंडल के प्रभारी अध्यक्ष को ज्ञापन देकर पारिश्रमिक भुगतान की मांग की है।

Badri Gautam

मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को लैपटाप दिया गया: मंडल के तात्कालीन अध्यक्ष ने मंडल से संबद्ध टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल के करीब 15 शिक्षकों को वीडियो व प्रश्न बैंक निर्माण के लिए उन्हें लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। वहीं निजी स्कूलों के शिक्षकों को अब तक भत्ता का भुगतान नहीं किया गया।

97 शिक्षकों के 9 लाख 70 हजार रुपए बकाया: मंडल ने सत्र 2020-21 में मप्र बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले निजी व सरकारी स्कूलों के शिक्षकों

पीईबी ने शुरू की कृषि विस्तार परीक्षा जांच, रिजल्ट में होगी देरी

नगर संवाददाता, भोपाल । प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के खाली पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इस एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप पीईबी पर लगे हैं। आरोपों के बाद पीईबी ने संबंधित परीक्षा की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद परीक्षा परिणाम आएंगे। ऐसे में परीक्षा परिणाम आने में देरी भी हो सकती है। पीईबी की परीक्षा में यह भी आरोप लगे थे कि उसने जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराई थी, वह अन्य राज्यों में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। इस संबंध में पीईबी ने दावा किया है कि परीक्षा एजेंसी के चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। सभी नियमों का

Badri Gautam

पालन करते हुए परीक्षा एजेंसी का चयन किया गया था। उधर, परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत की पीईबी ने जांच शुरू कर दी है। इसके तहत परीक्षा से संबंधित डाटा, सीसीटीवी फुटेज, सर्वर लॉग डिटेल की जांच की जा रही है। पीईबी का दावा है कि डाटा ट्रांसफर की सभी प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद संबंधित एग्जाम के परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।

कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी सरकार का फैसला

9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन

स्टार समाचार | भोपाल

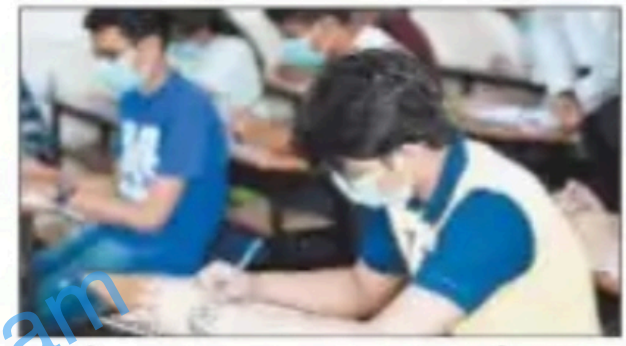

मध्यप्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा की तारीखों का लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐलान कर दिया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने ऑफलाइन परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। ऑफलाइन परीक्षाएं कराने को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली कर ली गई हैं।

भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा हैं। इसको लेकर सरकार ने रविवार को तीन शहरों में लॉक डाउन लगाने का फैसला किया है। बढ़ते संक्रमण के बीच 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं।

Badri Gautam

» नौवीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेंगी।

» कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक चलेंगी।

» बोर्ड परीक्षाओं की शुरूआत 30 अप्रैल से हो रही है। कक्षा10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षाएं 1मई से शुरू हो रही हैं।

12 अप्रैल से होंगी 10वीं-12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं

कक्षा 9वीं-11वीं के फाइनल एग्जाम के साथ ही दसवीं, बारहवीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 12 अप्रैल से 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी फाइनल एग्जाम से पहले प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी ऑफलाइन अयोजित होंगी।

कम संख्या वाले कॉलेज बंद करेगी सरकार

विंध्य, महाकौशल के सत्रह कॉलेजों पर संकट के बादल

विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र के 17 सरकारी कॉलेजों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सतना, सिंगरौली, कटनी, अनूपपुर, शहडोल, मंडला में चल रहे सरकारी कॉलेज कम छात्र संख्या के चलते शासन की आंख की किरकिरी बन गए हैं। लिहाजा इन महाविद्यालयों को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। सबसे बड़ा संकट उन सैकड़ो छात्रों के सामने आएगा, जिन्होंने इन संस्थाओं में प्रवेश ले रखा है। इन्हें शिक्षा के लिए मीलों की दूरी फिर तय करनी होगी।

Badri Gautam

स्टार समाचार | रीवा

सरकार ने प्रदेश के 51 सरकारी कॉलेजों को बंद करने की तैयारी कर ली है। इन कॉलेजों को बंद करने के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन को सूचना भी भेज दी है। सरकार ने कॉलेजों को बंद करने के पीछे उनमें विद्यार्थियों की उपस्थिति कम होना बताया है। सरकार की ओर से जो सूची जारी की गई हैं उनमें सतना, सिंगरौली के भी सरकारी कॉलेज शामिल हैं।

आए दिन किसी भी सरकारी संस्थान को निजी हाथों में सौंपने एवं बंद करने जैसी खबर अब आम हो चुकी है। इसी क्रम में सरकारी कॉलेजों को भी बंद किए जाने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी है। यहां सवाल यह उठ रहा है कि अगर सरकारी कॉलेज बंद होंगे तो उनमें पढ़ाने वाला स्टाफ कहां जाएगा। उधर, जिन कॉलेजों को बंद करने की बात सरकार कर रही है उनमें सैकड़ों विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। कॉलेज बंद होने के बाद उक्त कॉलेज के विद्यार्थियों का क्या होगा।

गिर जाएगा शिक्षा का ग्राफ

सरकार ने जिन कॉलेजों को बंद करने की तैयारी की हैं, उनके विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने की योजना भी बनाई है। अब प्रश्न यह उठता है कि बंद हुए कॉलेजों की दूरी दूसरे कॉलेज कई किलोमीटर दूर हैं। ज्यादातर बंद कॉलेज के विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जहां से वह अप-डाउन नहीं कर सकते हैं। ऐसे गांवों में शिक्षा का ग्राफ तेजी के साथ घटना तय है।

20 किलोमीटर में हो एक कॉलेज

उच्च शिक्षा विभाग सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी शहर या गांव में कॉलेज संचालन को लेकर 20 किलोमीटर का दायरा लिया जाता है। इस दूरी के बीच दूसरा कॉलेज संचालित नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं संबंधित क्षेत्र में हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की भी संख्या को दृष्टिगत रखा जाता है ताकि संबंधित क्षेत्र के छात्र या छात्रा कॉलेज में प्रवेश पा सकें। बताया जा रहा है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच की दूरी रखने के पीछे मुख्य वजह यह रहती है कि छात्र-छात्रा को अनावश्यक भटकना न पड़े।

संकाय के अनुपात में संख्या

विभागीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज में छात्र संख्या को लेकर कोई गाइड लाइन या मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है अलबत्ता संबंधित कॉलेज में संचालित किए जाने वाले विभिन्न संकायों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम छात्र संख्या का निर्धारण किया जाता है। ऐसे में संकाय के अनुपात में कम से कम संबंधित कॉलेज में छात्रों की संख्या दो सौ से ढाई सौ के बीच होनी चाहिए।

इन जिलों में बंद होंगे कॉलेज

सरकार ने जिन जिलों में कॉलेज बंद करने की तैयारी की हैं उनमें सतना में 4, सिंगरौली, डिंडोरी में 3-3, अनूपपुर, शहडोल, मंडला में 2-2, कटनी का 1 कॉलेज बंद किए जाएंगे।

न्यूनतम के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। फिर भी कम से कम दो सौ संख्या होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज को बंद करने पर एडी कार्यालय से प्रतिवेदन लिया जाता है। फिलहाल कॉलेजों को बंद करने के संबंध में हमारे यहां कोई जानकारी नहीं आई है।

पंकज श्रीवास्तव, एडी उच्च शिक्षा

बोर्ड परीक्षा में सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थी एक साथ देंगे परीक्षा

कई स्कूलों में रैंप की व्यवस्था नहीं होने से परेशान होंगे दिव्यांग विद्यार्थी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस बार बोर्ड के सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय एकसाथ रखा गया है, जबकि हर साल दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा अलग समय पर होती थी। हर साल सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक सामान्य विद्यार्थियों का समय होता था, वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों का समय दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक होता था।

उधर, हर साल प्रदेश से पांच हजार दिव्यांग विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होते हैं। इनमें करीब चार हजार को रैंप की आवश्यकता होती है लेकिन हालात ये हैं कि सरकारी स्कूलों में रैंप बनाने के आदेश दस साल पहले जारी किए गए थे, लेकिन अब तक नहीं बन पाए। प्रदेश के 58 फीसद सरकारी स्कूलों में रैंप नहीं बने हैं। इसमें दमोह, डिंडौरी, ग्वालियर जिले के कुछ स्कूलों में तो विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से रैंप बनना अत्यंत आवश्यक है। इनमें राजधानी के भी कई स्कूल शामिल हैं।

बता दें कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प बनाने के आदेश दिए थे। इस साल बोर्ड परीक्षा में करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में भी रैंप नहीं बने

पिछले वर्ष भी स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैंप बनाने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के 170 स्कूलों में से 74 स्कूल ऐसे पाए गए, जहां दिव्यांग बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें 51 प्राथमिक एवं 23 माध्यमिक स्कूल हैं। इन स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की संख्या 44 फीसद है, वहीं 20 फीसद स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं।

"भले ही इस बार सामान्य व दिव्यांग विद्यार्थियों की एक साथ परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन कोविड संक्रमण से बचाव के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों को उसी स्कूल में केंद्र दिया जाएगा, जहां पर रैंप बने होंगे।

– **उमेश कुमार सिंह**, सचिव माशिम

बीयू की परीक्षाएं पांच अप्रैल से होंगी शुरू

भोपाल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बरकतउल्ला विवि (बीयू) की परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतने होंगे। विवि प्रशासन ने परीक्षाओं को संचालित करने के विशेष इंतजाम किए हैं।

बीयू की द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं पांच अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षाएं तीन पाली में होंगी। हर पाली के बाद परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज किया जाएगा। बीयू ने सैनिटाइजर और हाथ धोने के पूरे इंतजाम किए हैं। विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने के पहले और बाद में आपस में चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करते हुए पाया गया तो बीयू उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई कर सकता है।

विवि द्वारा हर साल 100 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार 150 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचने के इंतजाम किए जाएंगे। विवि प्रशासन के साथ-साथ उड़नदस्ते भी साबुन और० सैनिटाइजर के साथ प्रसाधन कक्षों की साफ-सफाई पर नजर रखेंगे।

Badri Gautam

स्कूलों में स्वल्पाहार की व्यवस्था का आदेश निरस्त

भोपाल। अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी यह निर्देश दिए थे कि नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लगाई जाए। इसके अनुसार विद्यार्थियों को आठ घंटे स्कूल में बिताना पड़ता। विभाग ने आदेश में लिखा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता टिफिन आदि की व्यवस्था करने में सक्षम न होने के कारण उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने में समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए विभाग ने स्वल्पाहार की व्यवस्था की थी। स्वल्पाहार में चना, मुरमुरा, गुड़, भेल आदि की व्यवस्था की जानी थी। इसके लिए विभाग की ओर से राशि भी जारी की जा रही है। डीपीआइ आयुक्त जयश्री कियावत का कहना है कि अभी 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। जब खुलेंगे तब व्यवस्था करेंगे। -नप्र

Badri Gautam

आफलाइन परीक्षा पर उलझन बरकरार

असमंजस ● देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के फैसले का इंतजार

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अप्रैल में यूजी कोर्स की आफलाइन परीक्षा शुरू होना है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। वे ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आफलाइन और ओपन बुक परीक्षा के बीच विश्वविद्यालय फंसा हुआ है। मामले में सोमवार को कुलपति डा. रेणु जैन ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी चाही पर संपर्क नहीं हो सका। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग के फैसले का इंतजार है।

बीए, बीकाम, बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्स की फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर की परीक्षाएं एक अप्रैल से प्रस्तावित हैं। आफलाइन परीक्षा का विरोध तेज होने से विश्वविद्यालय की परेशानी बढ़ गई है। विश्वविद्यालय ने पिछले सप्ताह पत्र लिखकर विभाग के अधिकारियों से परीक्षा के मुद्दे पर राय मांगी है। जवाब अभी तक नहीं मिला है। परीक्षा में महज नौ दिन शेष हैं मगर आफलाइन और ओपन बुक परीक्षा को लेकर अधिकारी कुछ भी तय नहीं कर पाए हैं। सोमवार को परीक्षा नियंत्रक डा. अशेष तिवारी ने कुलपति डा. रेणु जैन से मुलाकात कर परीक्षा पर चर्चा की। कुलपति ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन बैठक में होने से बातचीत नहीं हो पाई। परीक्षा नियंत्रक का कहना है उच्च शिक्षा विभाग के जवाब का इंतजार है। वैसे आफलाइन परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। केंद्र के अलावा उड़नदस्ते भी बना दिए हैं।

10 दिन में पांच प्रदर्शन

आफलाइन परीक्षा का विरोध बढ़ गया है। दस दिन में विद्यार्थियों ने पांच बार प्रदर्शन कर दिया है। कुलाधिपति, मुख्यमंत्री को भी छात्र नेताओं ने ज्ञापन भेजा है। यहां तक कि छात्र नेताओं ने आफलाइन परीक्षा को लेकर सदबुद्धि यज्ञ भी विवि परिसर में किया। हस्ताक्षर अभियान से भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए विद्यार्थियों ने ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने का सुझाव दिया है।

20 अप्रैल तक बीएड कालेजों को भेजना है सूची, मई में शुरू होंगे आनलाइन प्रवेश

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अगले सत्र के लिए नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने एक मई से आनलाइन प्रवेश देने की योजना बनाई है। इसके तहत विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कालेजों की सूची बुलवाई है। यह काम बीस अप्रैल तक पूरा करना है। उसके बाद विभाग अपने स्तर पर कालेजों की मान्यता व संबद्धता का सत्यापन करेगा। नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने वाले कालेजों को प्रवेश के लिए अनुमति मिलेगी। उधर अधिकारियों का कहना है कि कालेज की सूची को प्रवेश के लिए मान्य किया जाएगा।

बीते दिनों 17 से 19 मार्च के बीच विभाग ने प्रदेशभर के हेल्प सेंटर प्रभारियों की गूगल मीट पर बैठक बुलाई। जहां उन्हें सत्र 2021-22 के लिए एनसीटीई मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश को लेकर दिशा-निर्देश दिए। 1 मई से 30 जून के बीच बीएड-एमएड, बीपीएड, एमपीएड सहित आठ पाठ्यक्रम में आनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए विभाग ने पूरी प्रक्रिया आनलाइन रखी है। काउंसिलिंग शुरू करने से पहले विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त कालेजों की सूची बुलवाई है। इसके लिए विभाग ने विश्वविद्यालय को एक से 15 अप्रैल के बीच कॉलेजों से सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करवाने को कहा है। इस अवधि में प्रबंधन को कालेज से जुड़ी जानकारी अपडेट करना है। विश्वविद्यालय को बीस अप्रैल तक संबद्धता और एनसीटीई की मान्यता संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करना है। बाद में ये सूची विभाग को आनलाइन भेजी जाएगी। फिर विभाग मुख्यालय अपने स्तर पर कालेजों की एनसीटीई और शुल्क विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का सत्यापन करेगा। 25 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी होना है। इसके आधार पर कालेजों को आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

Badri Gautam

नए सिलेबस के कारण मात्र छह फीसद रहा रिजल्ट

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) ने सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन परीक्षाओं के अंतिम परिणाम रविवार देर शाम जारी किए। सीए परीक्षा का रिजल्ट पुराने और नए कोर्स दोनों के लिए किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने ये दोनों परीक्षाएं दी हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं। सीए फाइनल में महज छह फीसद विद्यार्थी पास हुए हैं। कम रिजल्ट के पीछे नए सिलेबस को वजह बताई जा रही है, क्योंकि छात्र-छात्राओं को यह पता नहीं था कि किस प्रकार से प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। जानकारों के मुताबिक फाउंडेशन कोर्स में 24 फीसद रिजल्ट रहा है। विद्यार्थियों ने सफलता के पीछे शिक्षकों का निरंतर मार्गदर्शन मिलना बताया है। ऋषभ गंगवाल को आल इंडिया सातवीं, तन्या माहेश्वरी को आल इंडिया 34वीं और हितांशु गांधी को आल इंडिया 38वीं रैंक हासिल हुई है। देशभर से 27 हजार विद्यार्थियों ने सीए की परीक्षा दी थी, जिसमें इंदौर से 560 छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इनमें 72 विद्यार्थी दोनों ग्रुप में पास हुए हैं।

सीए का परिणाम

- **आइसीएआइ ने जारी किया सीए फाइनल और फाउंडेशन का परिणाम**
- **सीए फाउंडेशन कोर्स में 24 फीसद विद्यार्थी हुए पास**

नए सिलेबस से हुई परीक्षा : आइसीएआइ इंदौर ब्रांच के चेयरमैन सीए कीर्ति जोशी ने बताया कि नए सिलेबस से परीक्षा हुई है। इसका असर रिजल्ट पर देखा जा सकता है। फाइनल में कम विद्यार्थी दोनों ग्रुप में पास हुए हैं।

इंदौर-पुणे के शिक्षकों ने पढ़ाया

आल इंडिया सातवीं रैंक हासिल करने वाले ऋषभ गंगवाल बताते हैं फाइनल में पास होने के बाद अब प्लेसमेंट का इंतजार कर रहा हूं। लगातार 12-12 घंटे पढ़ाई की। नियमित कक्षा होने के बाद इंदौर-पुणे के शिक्षकों से आनलाइन क्लासेस ली। शिक्षकों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के अलावा कुछ महत्वपूर्ण टापिक भी समझाए। परीक्षा के दिनों में सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। मांडव निवासी ऋषभ के पिता नितिन गंगवाल बिजनेसमैन हैं।

Badri Gautam

रानी दुर्गावती गढ़ा स्कूल की एक और शिक्षिका को कोरोना

जबलपुर । रानी दुर्गावती स्कूल गढ़ा में एक अन्य शिक्षिका में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उन के अलावा दो अन्य महिला शिक्षिकाओं की तबीयत भी खराब चल रही है। हालांकि उनमें कोरोना संक्रमण मौजूद है कि नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इससे पहले एक महिला प्राध्यापिका को कोरोना संक्रमण हुआ था जिसके बाद ये दूसरा मामला स्कूल में सामने आया है।-नप्र

Badri Gautam

किताबों में शुरू हो गया कमीशन का खेल

परेशानी ● शहर के कई दुकानदारों ने निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के मनमाने दाम बढ़ाए

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले ही निजी स्कूलों के साथ पुस्तक विक्रेताओं की साठगांठ भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि 10-15 फीसद तक कमीशन स्कूल ने तय कर लिया है। इसकी भरपाई के लिए दुकानदारों ने फर्जी तरीके से दाम बढ़ा दिए है। किताबों में सालभर पहले के अधिकतम दाम लिखे हुए थे जिनके ऊपर मशीन की मदद से बढ़े हुए दाम दर्ज कर दिए गए हैं। ताकि मुनाफे के साथ स्कूलों में बंटने वाला कमीशन भी अभिभावकों से वसूल किया जा सके।

ऐसे होता है खेल: निजी स्कूलों के साथ महिनेभर पहले ही किताब-कापियां और स्कूल ड्रेस को लेकर सौदेबाजी हो जाती है। किताबों को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी होती है। निजी स्कूल हर साल नए प्रकाशक की किताब लगाते हैं। जहां से जैसा ऑफर मिलता है उसके मुताबिक किताब चला देते हैं। प्रकाशक से किताब लेने का काम दुकानदार करते हैं। स्कूल जल्द ही किताबों की सूची जारी नहीं करते हैं ताकि सभी स्कूल उसे न उपलब्ध करा सके। जिस दुकानदार के साथ स्कूलों का करार होता है उसी के पास संबंधित स्कूल की पुस्तकें मिलती हैं। इसके लिए दुकानदार अपने स्तर पर निजी प्रकाशक की किताबों में दर्ज अधिकतम मूल्य को छिपाकर उसके ऊपर नया दाम प्रिंट कर देता है।

स्कूलों को हर साल किताब बदलने का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी मैनेजमेंट स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है, लेकिन निर्धारित दाम से ज्यादा पर किताब नहीं बेची जा सकती है। प्रकाशक द्वारा निर्धारित दाम पर ही किताब बेची जानी चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर के माध्यम से दुकानों की जांच कर वाई जाएगी।

-घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी

19 स्कूलों ने नहीं दी किताबों की सूची, नोटिस

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। किताब और फीस का ब्यौरा प्रशासन से साझा करने से निजी स्कूल परहेज कर रहे हैं। 298 स्कूलों ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सीधे सूची जमा कर दी है, लेकिन 19 स्कूल मनमानी पर उतारू हैं, उनके द्वारा तय मियाद में सूची नहीं दी गई है। अब विभाग ने दोबारा उन्हें नोटिस देकर तत्काल सूची जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। स्कूलों द्वारा दी गई किताबों की सूची को डीईओ कार्यालय में सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है।

स्कूलों से मिली किताबों की सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते कर्मी। ● सौजन्य

इन स्कूलों ने नहीं दी सूची: सेंट ग्रेबियल हायर सेकंडरी स्कूल रांझी, नालंदा पब्लिक स्कूल धनवंतरि नगर, महर्षि विद्या मंदिर सेंचियर टाउन, प्रतिमा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, आदित्य कान्वेंट स्कूल गोपाल विहार, सेंट अगस्टीन लम्हेटाघाट रोड, रायल सीनियर सकंडरी स्कूल संजीवनी नगर, महर्षि विद्या मंदिर विजय नगर, रेयान इंटरनेशन स्कूल शांति नगर, जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजय नगर, द रायल हैरीटेज पब्लिक स्कूल, देहली पब्लिक स्कूल तिलवारा, ब्रिटिश फोर्ट फाउंडेशन, लिटिल किंगडम पनागर, सेंट जेवियर हाईस्कूल शांतिनगर, क्राइस्टचर्च डायोसियन घमापुर, सेंट फ्रांसिस घाना खम्हरिया, व स्टेम फील्ड स्कूल विजय नगर।

दो माह की फीस नहीं दी तो परीक्षा से बेदखल

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। दो माह की फीस जमा ना करने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्र को परीक्षा से बाहर कर दिया। प्रबंधन ने कहा कि पहले बकाया भुगतान करें, तभी उन्हें परीक्षा में बैठाया जाएगा। जब इस बात की जानकारी एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने आनंद नगर स्थित पंचवटी स्कूल किड्स किंगडम स्कूल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश हैं कि किसी भी छात्र को फीस को लेकर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी पर उतारू है। जिलाध्यक्ष विजय रजक ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में तत्काल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करें।

रद्दी चौकी स्थित स्कूल में प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआइ के पदाधिकारी। ● सौजन्य

किड्स किंगडम पंचवटी पब्लिक स्कूल प्रबंधन और छात्र के अभिभावक का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें स्कूल प्रबंधन द्वारा दो माह की फीस ना देने पर परीक्षा में शामिल करने से मना किया गया। छात्र की मां ने बताया कि उनके पति शहर के बाहर हैं जैसे ही आएंगे फीस जमा कर दी जाएगी लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। एनएसयूआइ को जब इस बात का पता चला तो अभिभावक के साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान, कौशल यादव, मोहसिन खान, सौरभ गौतम, अमित मिश्रा, शुभांशु कनौजिया, शुभम रजक, देवेंद्र काली, मोहम्मद अली, आदर्श अहिरवार आदि छात्र नेता उपस्थित थे।

Badri Gautam

विद्यार्थियों को मिली स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की प्रेरणा भरी जानकारी

आयोजन ● शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने संगोष्ठी

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जहां विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ उसमें शामिल सेनानियों की भी जानकारी दी गई। यह आयोजन प्राचार्य डॉ. एएल महोविया के निर्देशन में किया गया।

इन आनलाइन आयोजन में मुख्य वक्ता इतिहासविद डॉ. आनंद सिंह राणा रहे। जिन्होंने विद्यार्थियों को देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो बताया ही साथ ही यह भी बताया कि शहर के महापुरुषों व वीरों को देश की आजादी में क्या योगदान रहा है। डॉ. राणा ने बताया कि शहर के कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता है। किसी पाठ्यक्रम में भी उनका उल्लेख नहीं है। खासतौर पर युवाओं को अपने शहर के ऐसे महान वीरों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जिससे युवा इस बात को समझ सकें कि उनके शहर की गौरवगाथा कैसी रही है। डॉ. राणा ने कहा कि 1857 की पहली शहादत जबलपुर से हुई थी। गोंडवाना रियासत की रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने यह शहादत दी थी। दोनों पिता-पुत्र की वीरता की सत्यता युवाओं को पता होना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला सत्याग्रही थीं। शहर के सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सुभाषचंद्र बोस ने भी जबलपुर से ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी।

संयोजक डॉ. उषा मसराम व समन्वयक डॉ. अंकिता वोहरे ने बताया अपने शहर के विषय में युवाओं को पता होना चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में डॉ. सुनीता शर्मा, डॉ. जया बाजपेयी, डॉ. आर के श्रीवास्तव, डॉ. मनीषा डॉ. ज्योति श्रीवास्तव, डॉ संजय कक्कड़ का सहयोग रहा। विद्यार्थी मोहित शर्मा ने डॉक्यूमेंट्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिचय दिया। धन्यवाद डॉ. उषा मसराम ने किया।

शहीद दिवस स्मृति समारोह आज

जबलपुर। साहित्य अकादमी मप्र संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग, भोपाल पाठक मंच केंद्र - जानकीरमण महाविद्यालय के नेतृत्व में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के 75 वें वर्ष के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित शहीद दिवस स्मृति आयोजन किया जा रहा है। इसमें काव्य पाठ व भाषण प्रतियोगिता 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से श्रीजानकीरमण महाविद्यालय में होगी। जहां मुख्य अतिथि शरद चंद्र पालन, विशिष्ट अतिथि अभिमन्यु जैन, यूएस दुबे, राज सागरी, सुरेश मिश्र विचित्र, निरंजन द्विवेदी उपस्थित रहेंगे। आयोजन को संयोजन डॉ. अभिजीत कृष्ण त्रिपाठी करेंगे। संचालन डॉ. आनंद सिंह राणा द्वारा किया जाएगा।

Badri Gautam

एमपी-पीएससी • दूसरे दिन नहीं आए 32 परीक्षार्थी

भास्कर न्यूज | सतना

एमपी पीएससी की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन 32 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। ये सभी अभ्यर्थी राज्य लोक सेवा आयोग की इस प्रतिष्ठा पूर्ण परीक्षा का पहला चक्र सफलता पूर्वक पार कर चुके हैं। उल्लेखनीय है, पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एक तरह से क्वालीफाइंग एग्जाम है। वास्तविक परीक्षा मेन्स ही होती है। पहले दिन 27 परीक्षार्थी गैरहाजिर थे। माना जा रहा है कि सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र बिगड़ जाने के कारण दूसरे दिन 5 अभ्यर्थी नहीं आए, और इस तरह अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ कर 32 हो गई। एक्सीलेंस स्कूल व्यंकट नंबर वन स्थित परीक्षा केंद्र में सोमवार को मेन्स परीक्षा के तहत सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र था। एमपी पीएससी की मेन्स परीक्षा का अंतिम प्रश्नपत्र 26 मार्च को है। इस सेंटर में 496 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं।

परीक्षा केंद्र में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन

Badri Gautam

मास्क है जरूरी

परीक्षा केंद्र में दूसरे दिन सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने बैठक व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी नहीं जताई। परीक्षा पर्यवेक्षक संयुक्त कलेक्टर एचके धुर्वे ने बताया कि परीक्षार्थियों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के मद्देनजर एहतियाती तौर पर सख्त प्रबंध किए गए हैं। हर अभ्यर्थी और परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पूरे समय मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। मास्क लगा कर नहीं आने वाले परीक्षार्थियों के लिए मास्क की व्यवस्था भी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया रहा है। सैनिटाइजर के साथ-साथ सभी की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है।

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते शिक्षक।

Badri Gautam

भास्कर न्यूज | सतना

राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र त्रिपाठी की अगुवाई में जिले भर के शिक्षक धवारी चौराहे में एकत्रित हुए और रघुपति राघव राजा राम के गीत का गायन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पर मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि संयुक्त कलेक्टर हेमकरण धुर्वे को सौंपा। इस दौरान आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमोन्नति में लगाई गई रोक, त्रुटिपूर्ण जारी आदेशों के क्रियान्वयन में रोक व स्थानीय स्तर पर संविलियन शीघ्र करने की मांग भी शामिल थी। श्री त्रिपाठी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश स्तर व जिलास्तर की समस्याओं के निराकरण में यदि अब हीला-हवाली हुई तो हम अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे, उन्हें भी चैन की नींद नहीं सोने देंगें। स्थानीय स्तर पर आयुक्त कार्यालय से स्पष्ट निर्देशों के बाद भी 650 अध्यापकों की राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्त नहीं की जा रही है। जिसके विरुद्ध व्यापक जंग छेड़ी जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में शीला यादव, प्रीति गुप्ता, ऊषा सिंह, सुषमा शुक्ला, डा. मधू सिंह, माया सिंह, बिन्दू तिवारी, सरोज सिंह, मीरा मिश्रा, पुष्पा गोटिया, सरिता पटेल, बंदना सिंह परिहार, रंजना शुक्ला, श्याम कुमारी प्रजापति, वंदना साकेत, सुजाता यादव, नीलम सिंह, किरण त्रिपाठी, प्रीती शुक्ला, अंजना गौतम, सबीना रईस, कल्पना त्रिपाठी, शबाना कुरैशी, मनोरमा पाठक, राजा भैया त्रिपाठी, जेपी पटेल, ओंकार नाथ तिवारी, उमाशंकर गौतम, अखिलेश शुक्ला, आशीष सिंह, संतोष शुक्ला, चंद्रकांत द्विवेदी एवं अभिषेक सिंह आदि शामिल रहे।

नतीजा | 10वीं-12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में फेल हुए 12 हजार विद्यार्थी

भास्कर न्यूज | सतना

10वीं और 12वीं की अद्धवार्षिक परीक्षा में इस बार आधे से भी अधिक छात्र फेल हो गए हैं। विमर्श पोर्टल पर हाईस्कूल एवं हायर सेकंड्री स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा फीड किए गए रिजल्ट से यह पता चलता है कि बोर्ड के छात्रों की तैयारी अच्छी नहीं है। उधर प्राचार्यों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बदले गए पैटर्न पर परीक्षा कराई गई थी, इसलिए परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ है। विमर्श पोर्टल पर फीड किए गए अंकों के अनुसार कक्षा 12वीं में अद्धवार्षिक परीक्षा में 6 हजार 215 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 2 हजार 447 छात्र फेल हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 10वीं की परीक्षा में 18 हजार 466 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे, जिसमें 9 हजार 906 छात्र फेल हुए हैं। बताया गया कि जो छात्र ई-वन और ई-टू ग्रेड में आए हैं, उन्हें फेल माना गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी कुछ इसी प्रकार है। कक्षा 9वीं में 26 हजार 886 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें 14 हजार 463 छात्र फेल हुए। वहीं 11वीं में 10 हजार 178 छात्रों ने अद्धवार्षिक परीक्षा दी, जिसमें 3 हजार 258 छात्र फेल हुए हैं। अद्धवार्षिक के परीक्षा परिणामों को देखकर इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

तीन बार जारी हुए ब्लूप्रिंट

विभाग से जुड़े जानकारों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलें बंद थीं, इसलिए मंडल ने 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किया और परीक्षा का पैटर्न बदलकर ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। जिसके अनुसार तैयारी कराने में शिक्षकों को कम समय मिला। बाद में इस पैटर्न को भी बदल दिया गया और यह कहा गया कि पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी। लगभग इस काम में एक से डेढ़ माह का समय खराब चला गया। पुराने पैटर्न में पाठ्यक्रम की कटौती स्पष्ट न होने के कारण मंडल को तीसरा ब्लूप्रिंट जारी करना पड़ा। इससे कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों में भी असमंजस की स्थिति निर्मित हुई है।

अब 8 घंटे की पढ़ाई

15 दिसम्बर से स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की विद्यालय में पढ़ाई शुरू की गई है। अब तो 8 घंटे छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, इसके बावजूद भी शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं। शिक्षकों का कहना है कि जल्दबाजी में छात्रों का कोर्स तो पूरा हो जाएगा, पर वार्षिक परीक्षा परिणाम छात्रों का कैसा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शिक्षकों ने यह भी बताया कि इस बार का वार्षिक परीक्षा परिणाम भी उम्मीदों में खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि बीते सत्रों की तरह इस बार पढ़ाई ही नहीं हुई।

फैक्ट फाइल

कक्षा	परीक्षा में शामिल	अनुत्तीर्ण
» 9वीं	26886	14463
» 10वीं	18466	9906
» 11वीं	10178	3258
» 12वीं	6215	2447

आकांक्षा योजना के लिए भरे जा रहे आवेदन

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 10वीं में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए जेईई, नीट्स, एम्स क्लैट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने आकांक्षा योजना संचालित की जा रही है। इन छात्रों को जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में द्वि-वर्षीय कोचिंग दी जाती है। शासन द्वारा कोचिंग ले रहे छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ आवास सुविधा और कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं।

Badri Gautam

दो हजार से अधिक प्रोफेसर और लेक्चरर्स को पांच साल बाद भी सातवें वेतनमान का इंतजार

तकनीकी शिक्षा विभाग का मामला, कैबिनेट में लग सकती है मुहर

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत दो हजार से अधिक प्रोफेसर और लेक्चरर को पांच साल बाद भी सांतवा वेतनमान नहीं मिल सका है। जबकि इस अवधि में चार प्रमुख सचिव और दो मंत्री बदल चुके हैं। अब फाइल पांचवें पीएस के पास है।

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 70 पॉलीटेक्निक, सात इंजीनिरिंग कालेज और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में करीब 2200 प्रोफेसर और लेक्चरर कार्यरत हैं। ये पांच साल से सातवें वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कई बार फाइल तकनीकी शिक्षा विभाग से वित्त विभाग के बीच झूलती रही है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब विभाग के प्रमुख सचिव का प्रभार मुकेश चंद्र गुप्ता के पास है। बताया जाता है कि उनके पास सातवें वेतनमान की फाइल पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है।

वित्त विभाग से मंजूरीः मप्र तकनीकी शिक्षक संघ ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन पिछले तीन कैबिनेट में किन्ही कारणों से यह प्रस्ताव नहीं रखा जा सका है। अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट में इसे रखे जाने की उम्मीद है।

> तकनीकी शिक्षा विभाग के शिक्षक पांच वर्ष से सातवें वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं। इस मांग को विभाग के सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में लाया जा चुका है। यदि शीघ्र ही सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया तो आंदोलन करना पड़ेगा।
>
> **प्रो. उदय चौरसिया**, अध्यक्ष, मप्र तकनीकी शिक्षक संघ

> तकनीकी शिक्षकों के सातवें वेतनमान को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है, जो अंतिम चरण में है। इसमें शीघ्र निर्णय लिया जाकर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
>
> **मुकेश कुमार गुप्ता**, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग

Badri Gautam

सीएम राइज योजना पर सरकार करे पुनर्विचार

हरिभूमि न्यूज, कटनी

मप्र शिक्षक कांग्रेस की जिला शाखा की सामान्य सभा की बैठक संगठन कार्यकारी प्रान्ताध्यक्ष रामनरेश त्रिपाठी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुमान सिंह के संयुक्त आतिथ्य में आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के महामंत्री नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार के द्वारा 15 कि.मी. की परिधि में एक सर्व सुविधा युक्त विद्यालय खोले जाने की सी. एम. राइज योजना प्रारम्भ करने जा रही है, जबकि पूर्व के ही सुविधा युक्त विद्यालय के नाम से मॉडल स्कूल, उत्कृष्ट स्कूल, सुपर 100 स्कूल, सुपर 1000 स्कूल आदि संचालित है। इन संचालित विद्यालयों को सुविधा युक्त बनाते हुए यदि प्रत्येक प्राथमिक शालाओं को सी. एम. राइज योजना के तहत उन्नत एवं सुविधा जनक बनाया जावेगा वही परिणाम दायक होगा। अतः सरकार 15 कि. मी. परिधि में नवीन विद्यालय खाले जाने की योजना पर पुर्नविचार करे।

संगठन के संभागीय महामंत्री इलयास अहमद एवं अध्यक्ष अजय सिंह से सरकार के शिक्षकों का रूका हुआ मंहगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, क्रमोन्नति के आदेश जारी करने का आग्रह किया। बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षक/ शिक्षिकाओं ने पूर्ण निष्ठा के साथ शाला में अध्यापन कराते हुए कटनी जिले का वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ लाए जाने का संकल्प लिया।

सभा में हरिशंकर शुक्ला, बी. एम. तिवारी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र राय, रमाकांत पाठक, राजा जगवानी, रामखिलावन गर्ग, बी. डी. गौतम सहित शिक्षकगण मौजूद रहे।

Badri Gautam

भर्ती मामले में सेना के डाक्टर के खिलाफ होगी जांच

नई दिल्ली। सेना में जवानों की भर्ती के मामले में गड़बड़ी के आरोप में सेना के एक डाक्टर के खिलाफ सीबी आइ जांच करेगी। यह जानकारी देते हुए सरकारी सूत्रों ने बताया कि जवानों की मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में इस डाक्टर ने गड़बड़ी की थी। इस डाक्टर की तैनाती हरियाणा में है। सूत्रों ने बताया कि सेना भर्ती में लगभग 42 फीसद जवान पहली बार में मेडिकल परीक्षण पास नही कर सके। इन्हें एक माह बाद मेडिकल बोर्ड के समक्ष दूसरे टेस्ट का मौका दिया गया। इन अभ्यर्थियों में बहुतों ने परीक्षण में सफल होने के लिए दलालों के माध्यम से घूस दी। -एजेंसी

Badri Gautam

यूपी-बिहार समेत कई प्रदेशों से आए युवक फंसे

सेना में भर्ती से पहले लॉकडाउन की परीक्षा

हरिभूमि, जबलपुर।

लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशान सेना भर्ती में विभिन्न प्रदेशों से आए युवक हुए। रेलवे स्टेशन, गैरिसन ग्राउंड के बाहर डेरा डाले युवक भूख-प्यास से परेशान रहे। कई युवकों की चिंता इस बात की थी कि सोमवार को उनकी दौड़ है। उनके पास कोविड जांच की रिपोर्ट नहीं थी। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इन युवकों की सुध ली और इनके भोजन-पानी के प्रबंध किए।

सेना की ओर से सोमवार से रिलेशन भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें सेवारत, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवा, सैनिकों के आश्रितों को मौका दिया जाता है। सेना में की ओर से तकनीकी, सैनिक जीडी, सैनिक ट्रेड मैन श्रेणी में भर्ती लेनी है। इसके लिए इंदिरा गांधी आईजी ग्राउंड में वन एसटीसी की ओर से भर्ती की प्रक्रिया कराई जा रही है। हर अभ्यर्थी को 12 तरह के दस्तावेज लेकर पहुंचना है।

देश भर से युवक आए हैं भर्ती में शामिल होने

सेना की भर्ती में देश भर के विभिन्न राज्यों के युवक आए हैं। यूपी, बिहार, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के युवक आए हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस भर्ती में सभी को कोविड रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है। कई युवकों की भर्ती प्रक्रिया 24 व 25 की है, लेकिन एक ही ट्रेन सुविधा होने की वजह से मजबूरी में उन्हें काफी पहले आना पड़ा।

लॉकडाउन के चलते परेशानी

सोमवार से होने वाली भर्ती के चलते करीब डेढ़ हजार से ज्यादा युवक आए हैं। रविवार को जबलपुर में लॉकडाउन के चलते उन्हें काफी परेशानी हुई। युवकों को पैदल गैरिसन ग्राउंड जाना पड़ा। वहीं, बड़ी संख्या में युवक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर डेरा डाले हैं। रविवार दोपहर तक भूख-प्यास से परेशान युवकों के बारे में जानकारी होने पर सेना के अधिकारी आगे आए। आनन-फानन में इनके भोजन-पानी का प्रबंध किया।

भर्ती में आए युवकों का छलका दर्द

ग्राउंड में मौजूद बलिया के अभिषेक मिश्रा ने बताया कि उसकी भर्ती २४ मार्च को है। एक ही ट्रेन होने की वजह से पहले ही आना पड़ा। यहां पता चला कि लॉकडाउन लगा है। दोपहर तक खाने-पीने को कुछ नहीं मिला था। इसके बाद सेना के अधिकारी आए और भोजन का प्रबंध किया।

गैरीसन ग्राउंड में भर्ती के लिए आए युवक

गोरखपुर के कौड़ीराम, चौरीचौरा से आए यशवंत पाल, रामजनम शर्मा और बस्ती निवासी आनंद यादव ने बताया कि रास्ते में कुछ खाने के लिए घर से लाए थे। उसी से काम चला रहे हैं। यशवंत पाल की चिंता थी कि उनका कोविड जांच नहीं हुई थी। वहीं, रेलवे स्टेशन में सैकड़ों युवकों के साथ मौजूद मेरठ के जीवन पांडे, अभिषेक कुमार ने बताया कि सोमवार को भर्ती है। इस कारण रविवार की रात को ही आ गए थे।

Badri Gautam

पुरानी पेंशन और वरिष्ठता की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा

सिहोरा। शासकीय कर्मचारियों को 2005 से दी जा रही नई पेंशन नीति किसी भी स्थिति में कर्मचारियों के हित मे नही है,इसे बंद कर पुरानी पेंशन नीति को ही लागू किया जाए। राज्य शिक्षक संघ ने ऐसी मांग देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए की। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में क्रमोन्नति में रोक के आदेश को निरस्त करने की बात कही गई है। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर सिहोरा में जिला स्तरीय ज्ञापन सौंपते हुए संघ के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग विषय को लेकर ज्ञापन सौंपे गए है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 से जो नई पेंशन योजना शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू की है उसमें सेवानिवृत्ति उपरांत मात्र एक हजार रु से तीन हजार रु ही पेंशन मिलती है। कर्मचारियों और सरकार के द्वारा जमा कुल अंशदान का सेवानिवृत्ति पर मात्र 60 प्रतिशत और मृत्यु होने पर मात्र 20 प्रतिशत ही नगद प्राप्त होता है शेष राशि जीवन पर्यंत नगद प्राप्त नही की जा सकती है।ऐसे नियमों ने कर्मचारियों में भविष्य के प्रति खौफ पैदा किया है जिससे वे नई पेंशन नीति को बंद कर वर्ष 2005 के पूर्व की पेंशन लागू करने की मांग कर रहे है।

वहीं विगत दिवस आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अध्यापकों की क्रमोन्नति पर रोक से सम्पूर्ण संवर्ग आक्रोशित है और ऐसे कर्मचारी विरोधी आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे है। शिक्षकों ने अपने ज्ञापन में मांग की कि मुख्यमंत्री इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर विभाग की अध्यापकों के प्रति दोहरे व्यवहार को समाप्त करें। इस अवसर पर अरविंद उपाध्याय, रवि प्रकाश दुबे,श्याम यादव,राजेन्द्र दुबे,दीपचंद तंतुवाय,रामकिशोर हल्दकार, बी पी मिश्रा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

Badri Gautam

राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स को 5% मंहगाई राहत देने की मांग

मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

जबलपुर। पेंशनर्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने अपनी बहु प्रतीक्षित लंबित मांगों के लिए जिसमें जुलाई 2019 से केन्द्र के कर्मचारी एवं पेंशनर्स के समान पांच प्रतिशत मंहगाई राहत नहीं दिए जाने के फलस्वरूप राज्य के पेंशनर्स एवं कर्मचारी लम्बे समय से मप्र के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से निरंतर मांग करने के पश्चात भी अब तक भुगतान पर लगाई गई रोक को समाप्त नहीं कर आर्थिक रूप से परेशान करने पर पुनः अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मप्र वित्तमंत्री को संबोधित पत्र नीता राठौर डिप्टी कमिश्नर को सौंपकर मांग की है कि केवल मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को उक्त भुगतान से वंचित रखा गया है अतएव पूर्व से स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ता पर लगाई गई रोक को तत्काल समाप्त करते हुए भुगतान आदेश जारी किया जाए, जिससे राज्य के कर्मचारी, पेंशनर्स में व्याप्त आक्रोश समाप्त हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने मांग पत्र शीघ्र मप्र शासन को भेजने का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधि मंडल में जिला शाखा अध्यक्ष एचपी उरमलिया, शेषमणि पांडे, एके पिल्ले, एसपी शुक्ला, पुष्पा राजपूत, बीपी गौर, राधारमण तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

Badri Gautam

ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग, गीतांजलि कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन

Badri Gautam

गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में एक प्रोफेसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार को करीब 100 छात्राओं ने धरना दिया और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। वे दोपहर 12:30 बजे से दो बजे तक कॉलेज के मुख्य गेट के सामने पोस्टर लेकर बैठ रहीं और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं शामिल हुईं। छात्राओं का कहना है कि अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉलेज को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा है। ● **नवदुनिया**

न्याय : फोटो में छात्र की शर्ट पर लिखा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प का नारा हटवाने पर सजा

निलंबित टीचर को दो करोड़ 35 लाख रु. हर्जाना

माइकेल लेवेंसन

वॉल टाउनशिप, न्यू जर्सी में स्कूल शिक्षिका सूसन पार्सन्स कई साल से हाईस्कूल की इयर बुक से प्रशासकों के कहने पर विवादग्रस्त सामग्री हटाती रही। लेकिन, 2017 में उनके लिए एक नारा हटवाना भारी पड़ गया। इस मामले से अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक विचारों को लेकर तूफान खड़ा हो गया था। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल के सचिव के कहने पर एक छात्र की फोटो में शर्ट से डोनाल्ड ट्रम्प का नाम और उनका नारा-मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हटवा दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने पार्सन्स को निलंबित कर दिया। उन्होंने फैसले को अदालत में चुनौती दी। अब जिला शिक्षा बोर्ड ने पार्सन्स को दो करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना देकर मामला निपटाने पर सहमति जताई है।

जान से मारने की धमकियां

पार्सन्स द्वारा दायर मुकदमे में कहा गया कि नाम हटवाने के बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली थीं। उनके वकील क्रिस्टोफर इबेलर ने कहा, हमें खुशी है कि सूसन को इंसाफ मिल गया। वैसे, समझौते के तहत जिला बोर्ड ने कुछ गलत करने से इनकार किया है।

अपनी याचिका में पार्सन्स ने कहा उनसे दिसंबर 2016 में इयर बुक से छात्र की शर्ट के फोटो से ट्रम्प का नारा हटाने के लिए कहा गया था। जून 2017 में इयरबुक देखने के बाद छात्र ने ट्रम्प शब्द हटाने पर आपत्ति जताई। छात्र के माता-पिता ने भी एतराज किया। कुछ दिन के अंदर वॉल टाउनशिप में मामले ने जोर पकड़ लिया। 2016 और 2020 के चुनाव में इस इलाके से ट्रम्प को वोट मिले थे।

शिक्षिका ने याचिका में कहा कि इस बीच स्कूल प्रशासन ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे दोषी ठहराया। जिस छात्र की शर्ट से ट्रम्प का लोगो हटाया गया था,उसने 12 जून 2017 ट्रम्प के पसंदीदा टीवी कार्यक्रम-फॉक्स एंड फ्रेंड्स में हिस्सा लिया। उसी दिन स्कूल प्रिंसिपल ने पार्सन्स को निलंबित कर दिया। कुछ दिन बाद ट्रम्प ने फेसबुक पोस्ट में 'इयरबुक सेंसरशिप' की आलोचना की थी।

© The New York Times

Badri Gautam

हाईकोर्ट ने कहा- अफसरों और कर्मियों की तैनाती सरकार का विवेकाधिकार

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने कहा कि अफसरों और कर्मियों की तैनाती राज्य सरकार के विवेकाधिकार का विषय है। यदि याचिकाकर्ता को अनावेदक के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस निर्देश के साथ डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। सीधी निवासी पूर्व जनपद सदस्य बसंत मिश्रा की ओर से जनहित याचिका दायर कर सीधी जिले के रामपुर-नैकिन के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डॉ. संदीप भगत को बीएमओ बनाए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया डॉ. संदीप भगत बीएमओ पद के योग्य नहीं हैं। उनकी जगह किसी अन्य अनुभवी चिकित्सक को बीएमओ बनाया जाए।

Badri Gautam

ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कठिन प्रश्नों को हल करा रहे शिक्षक

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर

कोरोना के चलते शहर के स्कूल-कॉलेज 31 मार्च तक बंद हैं। इस दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए नगर निगम ने अपने 5 स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करा दी है। इस दौरान 13 रेग्युलर शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कठिन प्रश्नों को हल कराने उनकी मदद कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का स्मार्ट रूम शासकीय एलएनवाय स्कूल में बनाया गया है। ननि शिक्षा अधिकारी बीना वर्गीस ने बताया कि पढ़ाई के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है। ऑनलाइन अध्यापन के जरिए कक्षा नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाओं का कोर्स जनवरी माह में ही पूरा हो चुका है। उसके बाद जब स्कूल खुले तो विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया। शिक्षा अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में ऑनलाइट टेस्ट लिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए 32 वाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं।

ननि के 5 हायर सेकंडरी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएँ शुरू

Badri Gautam

वैक्सीनेशन के बाद शिक्षक व शिक्षिका की रिपोर्ट पॉजिटिव

स्कूल में हड़कंप, दोनों को किया होम क्वारंटीन, स्कूल में संचालित हो रही हैं कक्षाएं

रीजनल डेस्क, जबलपुर | वैक्सीन लगवाने के तत्काल बाद ही एक शिक्षक व शिक्षिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे स्कूल में हड़कंप की स्थिति है। वहीं चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन के दो डोज के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। एंटी बॉडी तैयार होने में समय लगता है। फिलहाल दोंनो को होम क्वारंटीन किया गया है।

जानकारी के अनुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालक शाला पाटन में पदस्थ शिक्षक व शिक्षिका को शुक्रवार को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। इसके बाद दोनों ने अपना कोविड टेस्ट कराया। इसमें दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया है कि स्कूल में कक्षाएं संचालित हो रही थीं। शिक्षक पाटन में ही रहते हैं, जबकि शिक्षिका जबलपुर से अपडाउन करती थीं। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस संबंध में बीएमओ एपी शुक्ला का कहना है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर है। शाला में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। अप्रैल में प्री बोर्ड एक्जाम में, जिसपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बेलखाड़ू: बुजुर्गों को रास आया टीका

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखाड़ू में 91 एवं निरंदपुर में 98 लोगों को टीका लगाया गया। टीका लगवाने वालों में अधिकांश बुजुर्ग शामिल थे। डॉ. नीलेश सूर्यवंशी ने बताया, 100 से 150 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में टीकारण बढ़ेगा। इसके अवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटंगी में भी 120 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।

पनागर: 106 वर्ष की बुजुर्ग का टीकाकरण

पनागर ब्लॉक अंतर्गत छत्तरपुर टीकाकरण केन्द्र में 106 वर्षीय महिला को टीका लगाया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी एसके दाहिया ने बताया कि ग्राम के पच्चो बाई उम्र 106 वर्ष को टीका लगाया गया है। टीका लगाने के बाद उन्हें आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। वे पूरी तरह स्वस्थ्य हैं।

बघराजी: केन्द्रों में लगा उम्मीदों का टीका

बघराजी, पिपरिया, सुनावल में टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सुपरवाइजर मनोज, श्रीकुमार बर्मन, नर्स हीरा नेहा सहू, माया यादव ने बताया कि बघराजी में 185, पिपरिया में 180, सुनावल में 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है।

गांधीग्राम: 13 सब हेल्थ सेंटर 4 पीएचसी में 2789 को वैक्सीन- कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब लोग खुद आगे आ रहे हैं। बीएमओ डॉ. दीपक गायकवाड़ ने बताया, ब्लाक के 13 सब हेल्थ सेंटर, 4 पीएचसी सेंटर व एक शासकीय अस्पताल में कुल 2789 लोगों सोमवार को वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन सेंटर पर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिला है। वैक्सीन लगवाने आये बुजुर्गों का कहना था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है और वो अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। गांधीग्राम में 102 व गोसलपुर पीएचसी में 231 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन के दौरान एएनएम माया कोल, ज्योति जेन्स, आशा कार्यकर्ता सुधा असाटी, मीना मिश्रा, हेमलता चौरसिया आदि मौजूद रहीं।

Badri Gautam

विवि में लाखों की बायोमेट्रिक मशीन हुई फेल

अधिकारी-कर्मचारियों को राहत, छात्र परेशान

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में लाखों रूपये की बायोमेट्रिक मशीन फेल हो गई। करीब दो साल पहले विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में चार बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, जो पिछले एक साल से बंद पड़ी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में लगी इन मशीनों को देखने वाला विश्वविद्यालय में कोई जिम्मेदार नहीं है। मौजूदा स्थिति में तो अब किसी कर्मचारी को इस बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाने की जरूरत भी नहीं रह गई।

गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कई दफा निर्देश दिए जाने पर वर्ष 2018 में विश्वविद्यालय ने बायोमेट्रिक मशीन लगाई है। प्रशासनिक भवन में लगी इन मशीनों में अंगूठा लगाने के निर्देश तब जारी हुए लेकिन शुरू से ही मशीन को लेकर कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज करा रखी है, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों को बायोमेट्रिक से न जोड़ना रहा। कर्मचारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने केवल कर्मचारियों को समय में बांधने की तरकीब निकाली है, जबकि

विवि के परीक्षा-कक्ष, एमपी ऑनलाइन चेम्बर में छात्रों की भीड़।

अधिकारियों को मनचाहे समय पर हाजिरी दर्ज कराने की छूट दे रखी है। इस गतिरोध के कारण बायोमेट्रिक मशीन लगाने के प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो सकी।

बेपटरी हो गई प्रशासनिक व्यवस्था

विश्वविद्यालय में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है। कोरोनाकाल के बाद से कई अधिकारी-कर्मचारियों में अलाली छा गई है। इधर, परीक्षा व गोपनीय विभाग के बाहर निरंतर पहुंचने वाले छात्र आये दिन जूझ रहे हैं। इन विभागों में जो कर्मचारी ठीक से काम कर भी रहे हैं, उनके पास अतिरिक्त बोझ है। वहीं, विश्वविद्यालय के कुछ विभाग ऐसे हैं, जहां छात्र जाते ही नहीं, उन विभागों के कर्मचारी मौज में है। कर्मचारियों के बीच ठीक से कार्यवितरण न होने पर इन छात्रों की समस्या निरंतर बढ़ रही है, जिनका निराकरण करने के बजाय वरिष्ठ अधिकारी अपने चेम्बर में सेफ हैं।

घर से नौकरी करने की मिली छूट

विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे विभाग हैं, जिनके ताले महीने में दो-चार बार ही खुलते हैं। इन विभागों में पदस्थ प्रत्येक कर्मचारी को करीब एक लाख रूपये वेतन मिलता है। इस बेरोजगारी के दौर में मोटी तनख्वाह पाने वाले कुछ कर्मचारी ईमानदारी से नौकरी नहीं करते बल्कि पूरे दिन घर में रोटी तोड़ते रहते हैं। सम्भवतः ऐसे ही कर्मचारियों को लाभान्वित करने विश्वविद्यालय प्रशासन ने बायोमेट्रिक मशीन का सिस्टम ही बंद करा दिया। ताकि महीने में एक बार आकर ये कर्मचारी आराम से हाजिरी भर सकें। बायोमेट्रिक मशीन की झंझट से इन कर्मचारियों को परेशानी न हो।

छात्रों के लिए उपयोगी नहीं रहे यूसिक व जेएनएन शोध केंद्र

विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा स्वीकृत शोध सहायक व सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं। विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू नीति शोध केंद्र की स्थापना है, जिसका उद्देश्य समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र व भूगोल विषय के शोधार्थियों की मदद करना है। इस केंद्र में पांच कर्मचारी पदस्थ हैं। बात और है कि वहां तक शोधार्थी छात्र पहुंचते ही नहीं, लिहाजा यह तो उपयोग समय के लिए केंद्र खुलता नहीं और खुलता भी है तो वहां छात्रों को मदद मिलती नहीं। इस केंद्र में शोध सहायक नलिन कुमार दुबे और डॉ रेखा शर्मा पदस्थ हैं। बी ग्रेड इन कर्मचारियों को व्याख्याता के समकक्ष करीब सवा लाख रूपये वेतन भुगतान हो रहा है। ऐसे ही यूसिक विभाग में भी अधिकांश समय ताला लटका रहता है। इस विभाग में तकनीकी अधिकारी डॉ प्रदीप कुमार सिंह समेत छह तकनीकी कर्मचारी पदस्थ हैं। हालांकि इनमें से कुछ एक-दो कर्मचारियों को परीक्षा विभाग में संलग्न किया गया है। बाकी शेष कर्मचारी पूरी तरह आराम की मुद्रा में हैं। बायोमेट्रिक मशीन फेल होने से इन कर्मचारियों के आराम में अब किसी तरह की कमी नहीं है।

> तीन-चार दिन अवकाश के कारण कर्मचारी नहीं थे जिससे छात्रों को दिक्कत हुई। अब आनलाइन कार्य विधिवत चल रहे हैं। बच्चों की समस्याओं का निराकरण हो रहा है। तकनीकी विभाग में कर्मचारी संलग्न हैं। जिनकी जरूरत पड़ती रहती है फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कर्मचारियों का ऐसा समायोजन हो जिससे छात्रों को दिक्कत न हो।
>
> **प्रो. राजकुमार आचार्य**
> **कुलपति अप्र सिंह विवि रीवा**

फिर लौट आये मूल विभाग

बताते हैं कि करीब चार माह पहले पूर्व कुलपति ने इन बेकाम विभाग के कुछ कर्मचारियों को परीक्षा व गोपनीय विभाग में संलग्न किया था। ताकि छात्रों के पैसे से वेतन लेने वाले कर्मचारियों से कुछ काम लिया जा सके परंतु प्रशासनिक व्यवस्था बदलते ही इनमें से कुछ कर्मचारी पुनः अपने मूल विभाग लौट गए, ताकि किसी तरह काम से बचा जा सके।

Badri Gautam

19 प्राइवेट स्कूलों ने नहीं भेजी पुस्तकों की सूची

हमारे प्रतिनिधि, जबलपुर|

प्राइवेट स्कूलों को कक्षाओं में लगने वाली किताबों की सूची मय प्रकाशकों के नाम सहित डीईओ कार्यालय भेजनी थी। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों को 19 मार्च तक का समय दिया था। उसके बावजूद 19 निजी स्कूलों ने डीईओ के आदेश को हवा में उड़ा दिया। इसके चलते डीईओ घनश्याम सोनी ने इन स्कूलों के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है और आज मंगलवार तक हर हाल में सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। डीईओ घनश्याम सोनी ने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर प्राइवेट स्कूलों में लगने वाली किताबों की सूची, प्रकाशकों के नाम सहित डीईओ कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय के रूम नंबर 4 सहित एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है।

समय सीमा निकलने के बावजूद भी नहीं दिया जवाब

Badri Gautam

मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के चुनाव में हंगामा, निर्वाचन स्थगित

26 मार्च को होना है चुनाव, नायक पर दूसरे गुट ने लगाए आरोप

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की चल रही चुनावी प्रक्रिया में सोमवार को मंत्रालय में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा मतदाता सूची में फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए किया गया। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मंत्रालयीन कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी समिति के चुनाव की अधिसूचना बीते शुक्रवार को जारी कर दी गई थी। निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त अवर सचिव संतोष ठाकुर व सहायक निर्वाचन अधिकारी आनंद भट्ट को बनाया गया था। 22 मार्च तक आपत्ति दावे आमंत्रित जा रहे थे। 23 मार्च को नामांकन पत्र भरे की तिथि थी। 26 मार्च को मतदान कराया जाना था। चुनाव प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल पैनल से सुधीर नायक व सुभाष चंद्र बोस पैनल से सुनील मरावी के बीच मुख्य टक्कर थी। सोमवार को मतदाता सूची में आपत्ति दावें का अंतिम दिन था। इसी दौरान सुनील मरावी गुट ने आपत्ति जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा किया गया है। इसमें दैवेभो कर्मचारियों के नाम जोड़े गए है। नायक पर मंत्रालयीन कर्मचारियों के काम नहीं करने के आरोप तक लगाए। मरावी गुट द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। चुनाव में अशांति व कोविड को देखते हुए चुनाव अधिकारी ने चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी। सहायक निर्वाचन अधिकारी आनंद भट्ट ने बताया कि कोविड व चुनाव में अशांति को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए है। आगामी तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

Badri Gautam

परीक्षा नियम से जुड़ी याचिकाओं का त्वरित निराकरण करें: सुप्रीम कोर्ट

जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2019 एवं राज्य सेवा नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली लगभग 43 याचिकाओं की सुनवाई 26 मार्च को जबलपुर उच्च न्यायालय में नियत है। मुख्य परीक्षा 21 मार्च से प्रारम्भ होकर 26 मार्च तक सम्पन्न होना है । राज्य शासन एवं पीएससी द्वारा याचिकाओं में जवाब दाखिल न करने के कारण उक्त याचिकाओं की सुनवाई 21 मार्च के पूर्व नहीं हो सकी जिस पर पीएससी के आवेदक कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा के माध्यम से सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल करके 21 मार्च से प्रारंभ होने वाली मुख्य परीक्षा को रोकने की राहत चाही थी।

Badri Gautam

उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें उच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 21 को अंतरिम आदेश पारित करके पीएससी की सम्पूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया है । उच्च न्यायालय में उक्त याचिकाओं की सुनवाई पूर्व से ही 26 मार्च नियत है इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका में हस्तक्षेप न करते हुए मप्र उच्च यायालय को निर्देशित कर प्रकरणों को त्वरित निराकरण करने का आदेश दिया गया है।

शिक्षक और छात्रों ने परिक्रमा पथ में शुरू किया सफाई अभियान

चित्रकूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सेवा मिशन के क्रम में मप्र शासन के राष्ट्रीय सेवा योजना मिशन के अंतर्गत महन्त प्रेमपुजारी दास कामता कामदगिरि हायर सेकेंडरी विद्यालय कामता चित्रकूट के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा कामदगिरि परिक्रमा पथ में सात दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया गया। विद्यालय के प्राचार्य केके बाजपेई ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की मंशा अनुरूप चलाए जा रहे कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत यह 7 दिनों का सफाई अभियान आज से शुरू किया गया है। जिसके तहत कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में पॉलीथिन व कचरा विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों द्वारा साफ करके जनमानस में पवित्र तीर्थ कामदगिरि एवं

Badri Gautam

मंदाकिनी को स्वच्छता बनाए रखने को प्रेरित करना एवं उसका संदेश प्रसारित करना है। यह अभियान निरंतर 7 दिनों तक चलाया जाएगा।

शहर से एक भी स्टूडेंट्स की नहीं लगी ऑल इंडिया रैंक

सीए फाउंडेशन और फाइनल का रिजल्ट जारी

लेक सिटी रिपोर्टर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन की परीक्षाओं का परिणाम रविवार देर रात को जारी किए, जिसमें भोपाल से एक भी स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक नहीं लगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने सीए परीक्षा क्लीयर की।

कंपनी सेक्रेटरी में 16वीं रैंक, लेकिन सीए में नहीं मिल पाई रैंक

अर्पित गोयल
57.75 प्रतिशत

अर्पित गोयल का कहना है कि मैं 2018 में कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 16 लेकर आया था तब से मैं कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूं। उसके बाद मैंने सीए करने का सोचा जिसके एग्जाम मई 2020 में थे। मैंने ब्रैक लिया और सीए की तैयारी की। लेकिन बीच में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मोरल थोड़ा डाउन हुआ। साथ ही रिवीजन में थोड़ी ढिलाई की वजह से रैंक नहीं बन पाई। अर्पित का कहना है कि मेरे पिताजी सीए हैं और मैं अब उनके साथ ही काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिला है।

मां के कहने पर मैंने सीए बनने के बारे में सोचा

Badri Gautam

सौम्या कौरव
61.88 प्रतिशत

सौम्या का कहना है कि मैंने मई 2020 के लिए तैयारी की थी और उससे पहले ही सारी क्लासेस कम्पलीट कर ली थी। 4 महीने सेल्फ स्टडी के लिए निकाले थे, मगर इसी बीच में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोंड होते-होते जनवरी में हुआ और फिर मैंने एग्जाम दिया। इंदौर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाली सौम्या का कहना है कि मां के कहने पर मैंने सीए बनने के बारे में सोचा और इसी दिशा में प्रयास करती रही। मां ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट की वजह से ही मैंने इस एग्जाम को क्रेक किया है।

कोरोना हुआ पर, हिम्मत नहीं हारी

नाम-सुयश मित्तल
58.88 प्रतिशत

सुयश का कहना है कि मैंने खुद पर भरोसा रखा। सेल्फ मोटिवेट होता रहा। मुझे भी कोरोना हो गया था। इससे मैं काफी डिप्रेशन और परेशानी में था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और 8-9 घंटे पढ़ाई करके इस एग्जाम को क्रेक किया। इसके साथ ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर मॉक टेस्ट से भी तैयारी की। माइंड चेंज करने के लिए पैरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता। उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना हैं।

स्कूल संचालकों के दबाब से पालक-छात्र-छात्राएं परेशान

मध्य स्वदेश ■ होशंगाबाद

निजी स्कूल संचालकों की शैक्षणिक दुकानों से फिर वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूल, पालकों पर बच्चों को फीस का दवाब बना रहे हैं। इसे लेकर मानसिक रूप से बच्चों पर भी दवाब बनता जा रहा है कारण कोरोना से परेशान पालकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं उसमें शिक्षा से जुड़े अभिभावकों सहित अन्य अभिभावकों की हालत वैसे भी ठीक नहीं जिन्हें वे- तन मिल रहा है, शैक्षणिक संस्थान अपने कर्मचारियों को वैसे भी आधा वेतन दे रहे हैं तो स्टाफ से कईयों की संस्थाएं छुट्टी कर चुका है यह हालत स्कूली संस्थाओं की ही नहीं अधिकांश निजी संस्थाएं अपने कर्मचारियों को वेतन पूरा नहीं दे रहे ऐसे में मां बाप के सामने पढ़ाई का खर्चा उनकी मनःस्थिति डगमगा देता और खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता, पालक भी क्या करें करोना ने तो सभी को अपने वश में कर रखा है, शांति निकेतन सहित अन्य कुछ संस्थाओं के खिलाफ पालकों ने फीस का दबाव बनाने पर शिक्षा अधिकारी को सवालों में घेर रखा है, हाईकोर्ट में भी न्यायालय के आदेश की अवमानना करने की शिकायत उन्होंने की है। अब इसके दूसरी तरफ नए शैक्षणिक सत्र की कहानी भी शुरू होगी। पालक और बच्चें दोनों असमंजस में है कि इस शिक्षा सत्र का परिणाम क्या होगा..? क्योंकि जिस तरह की शिक्षा नगर के स्कूलों ने दी है उसके परिणाम क्या रहे यह स्कूल बेहतर जानता है। वहीं यदि सरकारी स्कूलों की बात करें तो सिर्फ औपचारिकता महज दिखाई पड़ती है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने साल भर तनख्वाह पूरी ली, और आज भी ले रहे है। निजी स्कूलों के मालिकों ने शिक्षक को ऑन लाइन क्लास के नाम पर उनकी व्यक्ति गत जिंदगी खराब कर दी और मेहताना आधी पगार भी नही दी ऊपर से जेब के खर्चे से इंटरनेट डलवाकर शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाया क्या पढ़ाया.? वह बच्चे नही बता पा रहा। शिक्षकों ने भी इंटरनेट लिंक कॉपी करके फारवर्ड कर दी। इस कॉपी-पेस्ट लिंक ने पालक और बच्चों के डाटा खत्म करवा दिया ऐसी ऐसी लिंक दी है जिसमें 10 जीबी से अधिक के डाटा उपयोग हुए। बच्चे ने 6 विषय की लिंक प्रति दिन उपयोग की जबकि डाटा पैक ज्यादा से ज्यादा 2 जीबी प्रतिदिन का आता है। जो कि 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता है। शिक्षा की दुकान चलाने वालों ने सरकार को भी बहुत पैसा कमा कर दिया, इंटरनेट उपयोग के नाम पर निजी कंपनियों को काफी लाभ हुआ, निजी कंपनियों ने लॉक डाउन में इंटरनेट सेवाओ से बहुत लाभ मिला। इस इंटरनेट का उपयोग आम लोगो के लिए जेब पर बहुत भारी पड़ा। ऐसे में समझा जा सकता है जिस घर में 3 बच्चे है तीनों अलग अलग क्लास में पड़ते हैं, तीन फोन और 3 फोन में डेटा रिचार्ज एक सामान्य कमाने वाले के लिए बहुत कठिन साबित तो होता है..?

Badri Gautam

विहान ने छोटी उम्र में कर दिया ऐसा कमाल, मिला सम्मान

मध्य स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

कहते हैं मन में कुछ करने की दृढ इच्छाशक्ति हो तो छोटी उम्र में भी बच्चे कमाल कर जाते हैं। इंदौर के विहान ने महज 6 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिया, जिसे सुनकर लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। छह साल के विहान ने संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बदलते दौर के बीच आज जहां युवा पीढ़ी धर्म और आध्यात्म से दूर होती जा रही है, लेकिन इंदौर के नन्हें विहान की धर्म के प्रति रूचि देखते ही बनती है, महज 6 साल की उम्र में ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

विहान को संस्कृत के 55 श्लोक कंठस्थ याद हैं। जैन परिवार से ताल्लुक रखने वाले विहान की धर्म के प्रति ऐसी रूचि बढ़ी कि

Badri Gautam

उन्होंने आचार्य मानतुंग के भक्तामर स्त्रोत को कंठस्थ किया, इसकी प्रेरणा उसे उनके नाना-नानी से मिली, विहान की नानी उसे ऑनलाइन मंत्रोच्चार सिखाती रहीं, आज विहान भक्तामर स्त्रोत, लोग्गस पाठ, नवकार मंत्र और मंगल पाठ सही उच्चारण के साथ जाप कर लेते हैं। इस छोटी उम्र में ऐसी प्रतिभा को देखते हुए विहान का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नन्हें विहान का कहना है कि उनका आध्यात्म के साथ ही क्रिकेट से भी खासा लगाव है, विहान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के फैन हैं।

नानी ने सिखाया मंत्रोच्चार

विहान के नाना नानी ने सबसे पहले विहान की इस प्रतिभा को पहचाना, नन्हें बच्चे की धर्म के प्रति रूचि देखकर नानी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो रोज 1 घंटे ऑनलाइन तरीके से विहान को मंत्रोच्चार सिखातीं रहीं, विहान की संस्कृत में रुचि आश्चर्यजनक है, विहान के नाना नानी का कहना है विहान की इस प्रतिभा को देखकर दूसरे बच्चे भी मंत्रों का जाप करने लगे हैं, ये दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा देने का काम कर रहा है।

अब विश्व कीर्तिमान की बारी

विहान के पिता का कहना है इस उम्र के बच्चे मोबाइल गेम्स की दुनिया में ही खोए रहते हैं, लेकिन विहान रोजाना सुबह और शाम को श्लोक पाठ करता है। यही वजह है कि विहान का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज होने जा रहा है। उनकी कोशिश है कि विहान का नाम आगे चलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मे दर्ज हो,वहीं आध्यात्म के साथ ही विहान मोबाइल एप भी बना रहे हैं, वे अभी तक 50 मोबाइल एप बना चुके हैं जिसमें वॉटर रिमाइंडर एप, वॉश योर हेंड रिमाइंडर, बास्केटबाल एप, फाइंड द डिफरेंट एप शामिल हैं। बहरहाल विहान को इस छोटी सी उम्र में श्लोक पढ़ते हुए देख हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। उम्र के इस शुरूआती दौर में जिस तरह से विहान का आध्यात्म के प्रति लगाव है, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही नई पीढ़ी के सामने भी मिसाल पेश कर रहे हैं।

परीक्षा केंद्रों की जल्द जारी होगी लिस्ट

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा आयोजित होने वाली दसवीं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माशिमं ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। माशिमं जल्द ही परीक्षा केंद्रो को लेकर फाइनल लिस्ट जारी करेगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जिले से प्रस्तावित सेंटर की सूची माशिमं को भेज दी गई है। अब माशिमं ने चयनित सेंटर की लिस्ट जिलों की भेजने की तैयारी कर ली है।

Badri Gautam